साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

R.N.I. No.: MP/HIN/2006/20685

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

Webite: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9425125569
+91 9479535569

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 17 | अंक 28 | प्रति सोमवार इंदौर, 12 फरवरी से 18 फरवरी 2024 | पृष्ठ 8 | मूल्य 5/- रुपए

रूस युक्रेन, गाजा इजरायल, इराक व सीरिया पर अमेरिकी हमले

क्या सब बढ़ रहे हैं विश्व युद्ध की तरफ

अमेरिकी दादागिरी और चीन की हड़पो नीति धीरे-धीरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहे

पृथ्वी पर पुनः विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। जिसके पीछे अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विश्व को नियंत्रित करने अपना माल बेचने मोटी कमाई करने का भी भारी षड्यंत्र है। फिर अमेरिका यूक्रेन और इसराइल को अपने व्यावसायिक क्षेत्र साधने रूस आर्थिक सामाजिक व्यावसायिक और सामरिक रूप से और चीन को कमजोर करने एक तरफ यूक्रेन को हथियारों के साथ वित्तीय व अन्य प्रकार के युद्ध में रूस को खोखला कर बर्बाद करने के षड्यंत्र पर काम कर रहा है। जिन होती आतंकियों को ईरान समर्थन देकर मजबूत कर रहा है। बदले में अमेरिका ब्रिटेन ने इराक सीरिया पर आक्रमण किये हैं। यदि रूस और चीन जो अभी होती आतंकियों को मूक अप्रत्यक्ष समर्थन दे रहे हैं। यदि अमेरिका के विरुद्ध चीन और रूस मिलकर सीधे आमने-सामने हो जाएं तो यह युद्ध विश्व युद्ध में बादल सकता है।

इसराइल ग़ज़ा युद्धः हमास का सीज़फ़ायर के नए मसौदे पर क्या है रुख, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन ने क्या कहाः हमास ने कहा है कि ग़ज़ा में नए सिरे से सीज़फ़ायर (युद्ध विराम) के लिए प्रस्तावित मसौदे पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है. इस डील का मसौदा इसराइल, अमेरिका, क़तर और मिस्र ने तैयार किया है. इसके ब्योरे जारी नहीं किए गए हैं. रिपोर्टों के मुताबिक शुरुआत में बताया गया था कि इस मसौदे में छह हफ़्ते के संघर्ष विराम की बात रहेगी. ऐसा तब होगा जब फ़लस्तीनी क़ैदियों के बदले इसराइल के बंधक बनाए गए और लोगों को रिहा किया जाएगा. इसराइल और अमेरिका दोनों ने ही इस मामले में प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वो हमास के जवाब की समीक्षा कर रहे हैं.

इराक़ और सीरिया में अमेरिकी हमले के मायने क्या हैं?

अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में 13 जगहों पर हूती विद्रोहियों के 36 ठिकानों पर संयुक्त हमले किए हैं.

(शेष पेज 6 पर)

व्हाइट और ब्लैक पेपर

यूपीए और एनडीए में किसकी आर्थिक नीतियां बेहतर?

कांग्रेस और बीजेपी के बीच ताज़ा बयानबाज़ी में अर्थव्यवस्था एक अहम मुद्दा बन गई है

वाचालता झूठ और मक्कारी जो मोदी का गुण था। वह भाजपा का पर्याय बन गया। वैसे भी आरएसएस की उत्पत्ति से लेकर अभी तक आधारभूत नीतियों में पूंजीपतियों का पोषण और आम जनता का धर्म की आड़ में भ्रमित कर शोषण करना ही है जिसे पूरा करने के लिये आका के साथ पूरा गिरोह लगा हुआ है। बेशक देसी और विदेशी मीडिया जिसमें मुद्रित और दृश्य श्रव्य माध्यम मोटा धन लेकर सच से दूर जनता को भ्रमित करता वह मूल मुद्दे भूख बेरोजगारी शिक्षा स्वास्थ्य की वास्तविकता से दूर रख सत्ताधीशों के चरण चाट प्रस्तुति करने में लगा है। जिसे मोदी गिरोह अमित कल बता रहा है आजादी के बाद यथार्थ में देश की प्राकृतिक व मानव निर्मित संसाधनों की बर्बादी का काल बन गया। जिसे मोदी ने अपने जालसाज पूंजीपति मित्रों के लिए तू बेशक अमृत काल बना। परंतु देश, देश की जनता के साथ देश का राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर तरह से विनाश काल सिध्द रहा है। कांग्रेस भी मोदी के काले चिट्ठे को डर और दहशत में ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाई। मोदी के अमृत काल के बारे में 100 करोड़ भूखी बेरोजगार और महंगाई से त्रस्त जनता पिछले 10 वर्ष से देख ही रही है। कांग्रेस ने किस प्रकार प्रस्तुत किया है उसकी प्रस्तुतीकरण साल 2004 से 2014 के बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइडेट प्रोग्रेसिव अलायंस (यूपीए) सरकार के दौरान आर्थिक क्षेत्र में प्रदर्शन पर बीजेपी की नेतृत्व वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) ने एक श्वेत पत्र (व्हाइट पेपर) जारी किया है. इसमें उसने 2004 से 2014 तक के वक्त को 'विनाशकाल' कहा है, वहीं इसकी तुलना 2014 से लेकर 2023 के दौर से की है जिसे उसने 'अमृतकाल' कहा है. वहीं एनडीए के इस फ़ैसले के जवाब में कांग्रेस ने '10 साल-अन्याय काल' के नाम से एक ब्लैक पेपर जारी किया है जिसमें 2014 से लेकर 2024 के बीच की बात की गई है. दोनों ही दस्तावेज़ 50 से 60 पन्ने के हैं और इनमें आंकड़े, चार्ट, की मदद से आरोप और दावे किए गए हैं. बीजेपी के व्हाइट पेपर को यहां और यूपीए के ब्लैक पेपर को यहां पढ़ सकते हैं. कांग्रेस के अनुसार उसका दस्तावेज़ सत्ताधारी बीजेपी के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक 'अन्यायों' पर केंद्रित है जबकि सरकार का जारी श्वेत पत्र यूपीए सरकार की आर्थिक ग़लतियों पर रोशनी डालने तक सीमित है. अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी का कार्यकाल भारी बेरोज़गारी, नोटबंदी और आधे-अधूरे तरीक़े से गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) व्यवस्था लागू करने जैसे विनाशकारी आर्थिक फ़ैसलों, अमीरों-ग़रीबों के बीच बढ़ती खाई और निजी निवेश के कम होने का गवाह रहा है.

(शेष पेज 6 पर)

पिछले 20 सालों में 4 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मियों की बर्बादी

कमीशनखोरी में संविदा आउटसोर्स ठेका कर्मियों शोषण

आइएएस, अधिकारियों, मंत्रियों के कमीशन के साथ 28% जीएसटी भी

प्रदेश के साथ पूरे देश में शासकीय विभागों में पिछले 30 साल से नियमित भर्तियां न करने, सरकारी विभागों में काम के 4 से 10 गुना हो जाने, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की मौत बीमारी और सेवानिवृत्ति के कारण शासकीय विभागों में वर्तमान में मात्र नियमित 20% स्टाफ बचने के कारण काम करवाने के लिए संविदा आउटसोर्स ठेके पर कर्मचारियों अधिकारियों की भर्ती की जाने लगी। स्वाभाविक है भर्ती करने वाला हर अधिकारी जिला स्तर से लेकर मंत्रालय में बैठे घोर धूर्त भ्रष्ट भारतीय प्रताड़ना सेवा अधिकारियों, विभागीय मंत्री व मुख्य मंत्रियो तक के लिए मोटी कमाई का साधन बन गया। इसके लिए बहुत तरीके से श्रम कानून में भी परिवर्तन किया गया। यही हाल नियमित कर्मचारियों अधिकारियों की पदोन्नति में भी किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में स्थगन की आड़ लेकर पिछले 8 सालों से पूरे प्रदेश के सभी विभागों में मोटी कमाई करने के लिए खाली पदों को भरने और काम चलाने के लिए प्रभार दो, प्रभार लो के खेल से भी लगभग दो अरब रुपए साल की मोटी कमाई की जा रही है। परिवार का यह खेल केवल राज्य सरकार के विभागों में काम करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों इंजीनियर डॉक्टर वैज्ञानिकों निरीक्षकों के साथ हीकिया जा रहा है और खेल में तृतीय श्रेणी कर्मचारी को प्रथम श्रेणी संभागीय जिला अधिकारी के रूप में बिना स्थाई पदोन्नति के पदस्थ करने के साथ सभी प्रभारी से महीने की किस्त वसूली या ई एम आइ के रूप में भी वसूलिया रही है और यह खेल भी लगभग हर महीने एक अरब रुपए का चल रहा है। जिसमें गृह, लोनिवि, लोस्वायां, शिक्षा स्वास्थ्य वन कृषि उद्यानिकी, जसंवि, ग्रामीण विकास वाणिज्य कर, महिला बाल विकास, आबकारी, पंजीयन, विद्युत कंपनियों, गृह निर्माण मंडल, खनिज स्वास्थ्य आदि सभी विभागों में प्रभार के नाम पर मोटा भ्रष्टाचार लूट वसूली का खेल भी खेला जा रहा है। परंतु यह खेल आईएएस आईपीएस आईएफएस व उच्च प्रथम श्रेणी अधिकारियों में नहीं चल रहा वहां नियमित्त समय पर पदोन्नतियां दी जाती हैं। वेतन भत्ते महंगाई आदि में भी उनकी लूट का तांडव चलने के साथ प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारियों का भरपूर शोषण किया जाता है। (शेष पेज 7 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

कानून कमाई व जनता के शोषण के हथियार

कानून की सैद्धांतिक परिभाषा जनता की सुरक्षा और शासन तंत्र को चलाने की लिखित दस्तावेज नहीं रह गए। अब कानून सत्ताधीशों के लिए अपनों के पोषण और निरीहों के शोषण का हथियार बन चुके हैं। अब अविश्वसनीय निरर्थक हो गए सारे जिला एवं सत्र न्यायालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक जो कानून का पालन कर जनता समाज और राष्ट्र को सामाजिक आर्थिक नैतिक न्यायिक विश्वास के दम पर न्याय देने की शासकीय व्यवस्था थी। अब ये जनता के विश्वास के आधार बिंदु पूंजी पतियों सत्ताधीशों की रखैल बन कर रह गये हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन ने कहा था न्यायालय न्याय के मंदिर नहीं जूते अड्डे बन चुके हैं जो जितना धन खर्च करेगा उसे उतना न्याय मिलेगा।

1965 के बाद इस देश में सारे कानून पूंजीपतियों बहुराष्ट्रीय कंपनियां के इशारे पर जनता को बिना बताए दिखाए और पूछे मोटा धन हजम कर जनता के शोषण के लिए थोपे। अंग्रेजों ने इस देश में भारतीय नागरिक सेवा परीक्षा के माध्यम से अधिकारियों को जो आगम आय संग्रहण के लिए चुने जाकर जिलों संभागों के कलेक्टर कमिश्नर के रूप में नियुक्त किए थे इन हरामखोर जालसाजों अपने आजादी के समय देखा की कोई इन पर नियंत्रित करने वाला सक्षम अधिकारी नेता मंत्री नहीं है इन्होंने अपने आप को भारत का प्रशासनिक सेवा अधिकारी घोषित कर असीमित अधिकारों का संचयन कर लिया जिसे उसे समय के चुने हुए नेता मंत्री विधायक सांसद समझ नहीं पाए और यह सर्व शक्तिशाली बन गए। आजाद भारत मेंयह प्रशासनिक सेवा अधिकारी जनता को कीड़े मकोड़े सरकारी राज्यों के कर्मचारियों अधिकारियों को भेड़ बकरियां मां कानूनी की अपनी तरीके से व्याख्याकर हर कदम पर कानूनों की आड़ में लूट और कमाई का तांडव कर रहे हैं। यथार्थ में कानून और संविधान इनके लिए पिछाड़ू जेब में पड़ी रखैल से ज्यादा कुछ भी नहीं।

अपनी मोटी कमाई के लिए पूंजी पति और सत्ताधीश नेताओं मंत्रियों के इशारे पर यह हरामखोर जालसाज किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हाल ही में बहुराष्ट्रीय कंपनी और पूंजीपतियों के मोटे फायदे शॉपिंग मॉल चलाने उनसे महीना खाने के लिए 2006 में थोपे गए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम जिसमें अब उसकी भूमिका खत्म हो जाने के बाद में भी आपने इंदौर में देखा किस प्रकार से छोटे व्यापारियों दुकानदारों विक्रेताओं उद्योगों से मोटी वसूली करने, खत्म करने और अधिकारों की आड़ में मोटी कमाई करने सौंफ को रंगीन किए जाने के कारण जिस खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी को केवल नमूने लेने और जांच प्रयोगशाला में भेजना और खराब पाए जाने पर न्यायालय में प्रकरण लगाने का अधिकार था। उसने दूसरे व्यापारियों से मोती वसूली करने दर्शन देने सौंफ को रंगीन करते पाए जाने पर उसे पूरी फैक्ट्री को अपने आप की जागीर समझ हरामखोरों ने बिना कानून का पालन किये अनेकों वहां कार्यरत लोगों को बेरोजगार कर फैक्ट्री ही तो होगी जिसमें नगर निगम पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भरपूर तांडव किया। पीड़ित पक्ष को तत्काल उच्च न्यायालय में जाने के साथ जिला एवं सत्र न्यायालय में भी मुकदमा ठोकना चाहिए। इसके साथ ही सारे के सारे छोटे व्यापारियों विक्रेताओं उद्योगों कोन केवल इंदौर प्रदेश पूरा देश बंद कर उनके इस तांडवों के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए आपको बता दूंकि इस भारतीय प्रधान सेवा के अधिकारियों को सबसे ज्यादा डर जिला एवं सत्र न्यायालय का होता है कोई भी मुकदमा अगर आपने वहां फाइल कर दिया तो इन हरामखोरों की औकात नहीं है कि यह जिला हम सत्र न्यायालय में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज भी करवा सकें। बेशक कानून निरीहों के शोषण का हथियार होते हैं। परंतु सबके लिए समान होते हैं। सत्ता पद धन संपत्तियों कब किसका साथ छोड़ सड़क पतला पटकेगी समय का कोई भरोसा नहीं परंतु अधिकारों की लड़ाई में और संघर्ष का भरोसा आवश्यक है छोटे व्यापारियों उत्पादकों को डरने की अपेक्षा उन्हें कानून से जंग लड़नी पड़ेगी। जिसका यह हरामखोर दुरुपयोग करते हैं।

अपनी मोटी कमाई कर जिन कानूनों का दुरुपयोग कर इन्होंने हीं हरदा के अग्रवाल बंधुओं को बारूद के पटाखे की मौत की फैक्ट्री चलाने की छूट दी। जिसमें छोटी सी चूक ने 10000 से ज्यादा जिंदगियों को अकाल मौत का शिकार बना दिया। उस 15 वर्षों से ज्यादा समया चलने वाले इस कारखाने कुछ चलाने से संबंधित सभी शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों जिसमें पूर्व और वर्तमान के श्रम, कारखाना, क्षेत्र के थाना, पालिका निरीक्षक से लेकर पटवारी और राजस्व निरीक्षक तहसीलदार सहायक जिला व जिलाधिकारी, संभागायुक्त क्षेत्र का विधायक सांसद मंत्री से लेकर आसपास के जो 500 से 2000 तक की आबादी के पांच सात गांव जो सब धमाके के कारण नष्ट हो गए के पंचों सरपंचों तक सभी को अभियुक्त बनाया जाना चाहिए। क्योंकि सब कानून का मजाक बनाने और उसे कानून की आड़ में मोटी कमाई कर रहे थे तो हजार उन लोगों की मौत के लिए वह सब भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना शासकीय कर्मचारी अधिकारी।

वन विभाग में भ्रष्ट वनेलों की भरमार

पौधारोपण, जमीनों, वन उत्पादन संपत्तियों की हेर फेर से मोटी कमाई

सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर पीसीसीएफ से लेकर सीसीएफ और डीएफओ तक सब करते हैं जालसाजी

प्रदेश के वन विभाग में प्रदेश की वन संपत्तियों वन उत्पादन वृक्षों कीमती जड़ी बूटियों से लेकर यथा जर जंगल जमीन जल जानवरों से लेकर वन क्षेत्र में आने वाली खदानों, जिसमें कीमती भूमि की हेर फेर से करने से मोटी कमाई करने तक हर कदम पौधारोपण, वृक्षों पर नंबरिंग बचाओ वनों की साफ सफाई तेंदूपत्ता बिनवन कर्मियों को आने-जाने के लिए कच्ची सड़कों के निर्माणमजदूरों का भुगतान करने से लेकरशहरी क्षेत्र से लगी वन भूमि काअतिक्रमण करवानेवनों में वन भूमि कोकिसानों को पट्टे पर देनेतक से मोटी कमाई की जाती है और यही कारण हैकि जब सीसीएफ डीएफओया पीएससी अप से जानकारी मांगी जाती हैतो जानकारी देने की अपेक्षा बहाने बनाए जाते हैं।

दूसरी तरफ भारतीय वन सेवा अधिकारी यथार्थ में भारतीय वन खाओ सेवा अधिकारी हैं। यहां पर भी प्रभात के खेल के साथ मेंस्थानांतरण और पदस्थी में भी मोटा लेन देन होता है।

कैपा प्रोजेक्ट के प्रभारी ने इंदौर के अफसरों पर जताई नाराजगी, कहा- अब तक क्यों नहीं की कार्रवाई?

कंपेल : पौधारोपण में भ्रष्टाचार की जांच करेगी उज्जैन सीसीएफ और टीम

कंपेल में कैंपा प्रोजेक्ट के तहत किए गए पौधारोपण में भ्रष्टाचार के मामले में वन विभाग इंदौर के अफसरों द्वारा लीपापोती की कोशिश काम नहीं आई। शिकायत भोपाल पहुंचने के बाद प्रोजेक्ट के प्रभारी पीसीसीएफ ने इंदौर के अफसरों से नाराजगी जताते हुए सवाल पूछा कि उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? वहीं, इस मामले की जांच के लिए उज्जैन सीसीएफ और उनकी टीम को जिम्मेदारी दे दी।

चोरल रेंज के कंपेल में क्षतिपूर्ति के रूप में 79 हजार पौधे लगाए गए थे, जो 1.17 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसे कैंपा प्रोजेक्ट के तहत सीसीएफ ने गोद लिया था। हालांकि सीसीएफ ने ही जब डीएफओ के साथ मौका मुआयना किया।

हालांकि दस्तावेज में मेंटनेंस के सभी काम करना बताए गए थे। डीएफओ ने दिसंबर 2023 में रेंजर जयवीर सिंह से जवाब मांगा था, लेकिन कार्रवाई नहीं की।

इस मामले में 'जहां लगाए थे करीब एक लाख पौधे, वहां अब केवल घास' शीर्षक से खबर प्रकाशित की। इसके आधार पर वन विभाग के ही पूर्व अधीक्षक शंकर नाईक ने रेंजर के साथ एसडीओ केके निनामा के खिलाफ भी सीएम से लेकर वन विभाग के आला अफसरों तक शिकायत की थी।

तब सीसीएफ ने कहा थी कि समिति बनाकर जांच करवाई जा रही है। हालांकि न तो समिति बनाई और न ही जांच शुरू की। सीसीएफ ने बाद में कहा कि जो अनियमितताएं हुई थीं, उन्हें सुधार लिया है। इसके बाद नाईक ने भोपाल जाकर कैंपा प्रोजेक्ट के प्रभारी पीसीसीएफ महेंद्र सिंह धाकड़ को मामला बताया था।

जानकारी के अनुसार, पीसीसीएफ ने इंदौर सीसीएफ और डीएफओ को कॉल कर नाराजगी जताते हुए कहा कि जब अनियमितता पाई गई और जांच में यह सिद्ध भी हुआ तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? इसका जवाब अफसरों से मांगा है। इसके बाद पीसीसीएफ ने उज्जैन सीसीएफ के नेतृत्व में स्वतंत्र कमेटी बना दी, जो मामले की जांच कर रिपोर्ट सीधे उन्हीं को देगी।

जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी कार्रवाई कंपेल के जंगल में कैंपा प्रोजेक्ट के तहत करवाए गए पौधारोपण में अनियमितताएं पाई गई हैं। उज्जैन सीसीएफ की टीम इसकी जांच करेगी और रिपोर्ट मुझे देगी। रिपोर्ट के आधार पर दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी।

- महेंद्र सिंह धाकड़,
पीसीसीएफ और प्रभारी
कैंपा प्रोजेक्ट भोपाल

हरदा हादसा

जिम्मेदार अधिकारियों-नेताओं को भी मिले सजा

हरदा का पटाखा फैक्ट्रीकांड जिसमें 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई सौ आजू-बाजू के मकान साफ हो गए। आसपास के रहवासियों के अनुसार 1000 से ज्यादा बच्चे फैक्ट्री में काम करते थे। क्या किसी श्रम अधिकारी औद्योगिक स्वास्थ्य एवं संगठन निरीक्षक के साथ उद्योग विभाग कलेक्टर तहसीलदार पटवारी नगर पालिका के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी वहां का श्रम निरीक्षक किसी को का पता नहीं था? वहां से 5 लाख रु. प्रतिमाह वहां की सहायक श्रम आयुक्त जैस्मिन अली सितारा वहां का श्रम अधिकारी अग्रवाल बंधुओ से वसूलता था। आखिर रु. 5 लाख महीने श्रम विभाग को कोई उद्योगपति कैसे व क्यों देगा? बिना बड़े भारी श्रम कानूनों के उल्लंघन और मोटी कमाई के। वहां से लगभग 25 लाख रुपए महीने की और रिश्वत बाती जाती थी सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को जिसका हिस्सा भोपाल तक पहुंचता था। इसीलिए हजारों आदमी मरने के बदले में भी 11 आदमी दिखाए।

न केवल अग्रवाल बंधुओं को बचाने, हजारों लोगों की अकाल मृत्यु के पाप वह सतत मोटी कमाई करने के भ्रष्टाचार को छुपाने स्वयं ही वहां का तहसीलदार क्विंटल से वहां बने हुए पटाखों को नहर में फिकवा रहा था। लगभग 100 क्विंटल से ज्यादा पटाखे भोपाल के बड़े आईएएस, आईपीएस सरकार में बैठे मंत्रियों व क्षेत्रीय नेताओं के अभी हर साल पहुंच जाते थे यह सिलसिला पिछले 15-20 सालों से चल रहा था वह सारे अधिकारी भी हरदा की मौतों के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं। जितना हरदा का कलेक्टर लेबर ऑफिसर एसपी वहां का थानेदार आधी आधी बेशक सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी अपने पापा को ढकने के लिए पर यह मोहन यादव नया मुख्यमंत्री भी प्रदेश के लिए पनौती साबित हो रहा है 2 महीने में ही बड़े-बड़े बस दुर्घटनाएं और यह हरदा के हादसे हो गए।

हरदा के हादसे के आड़ में प्रदेश भर के सारे एडीएम एसडीएम एसपी डीएसपी कलेक्टर सब के सब सभी पटाखा व्यापारियों को लूटने में चिपक गए हैं। जबकि उनकी सहमति और संरक्षण सहयोग से ही वह अपना पटाखे का कारोबार करते हैं। बस जब कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो ही कुछ दिन हल्ला मस्त हैऔर उसके बाद मेंसब ठंडा हो जाता है पर इन हरामखोर जालसाजों को जनता की सुरक्षा उनके जानवरकाल म्यूट के तांडव से कुछ लेने देना नहीं इन्हें तो लूट का बहाना मिलना चाहिए और यह सारे सरकारी अधिकारी शमशान के वह चांडाल हैं।

जिन्हें बूढ़ा मारे या जवान बस लूटने से काम।

अपराधियों अवैध व्यापार करने वालों भू कॉलोनी पटाखा शराब ड्रग शिक्षा नौकरी आदि अनेकों किस्म के माफियाओं कोअपनी मोटी कमाई के लिए पालना संरक्षण देना इन्हीं का काम हैऔर फिर अपनी बहादुरी दिखाने के लिए इनको पकड़ कर सजा दिलवाना भी इनकी ही जालसाजी भ्रष्टाचार की बहादुरी का हिस्सा है।

पुलिस ने दो और आरोपियों को खंडवा से दबोचा

हरदा पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में मरने वालों की सरकारी संख्या बढ़कर 13 हो गई है. अधिकारियों को दोनों मृतकों की पहचान करने में मुश्किल हो रही है, इसलिए दोनों शवों का डीएनए करवाया जाएगा, जिससे उनकी वास्तविक पहचान हो सके. इस मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया. फैक्ट्री में ब्लास्ट के इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने खंडवा से गिरफ्तार किया है.

पुलिस ने पटाखा फैक्ट्री के मैनेजर 35 वर्षीय के आशीष पिता राधाकिशन तमखाने और उसके सगे भाई 31 वर्षीय अमन पिता राधाकिशन तमखाने को गिरफ्तार किया है. ये दोनों आरोपी खेड़ीपुरा के रहने वाले हैं और पुलिस ने इनकों खंडवा से हिरासत में लिया है. अब इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है. इससे पहले पुलिस इस मामले में फैक्ट्री संचालक राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल, मन्नी उर्फ रफीक खान को गिरफ्तार कर चुकी है.

---

16 ड्रमों में मिले सुतली बम

इधर पुलिस को पटाखा फैक्ट्री के पास से मलवा हटाने के दौरान 16 ड्रमों में हजारों सुतली बम मिले, जिन्हें प्रशासन ने पानी में डालकर नष्ट कर दिया है. हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट में पीड़ित बेघर लोगों ने चक्का जाम करि दिया. चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया. मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने प्रदर्शकारियों से बातचीत कर समझाइश दी. करीब आधे घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद लोग मान गए.

नेहा ने खो दिए माता-पिता

फैक्टरी के पास ही नेहा चंदेल रहती है। नेहा ने बताया, 'मैं कॉलेज जा रही थी, तभी एक धमाका हुआ। दो बहनें और माता-पिता घर से भागे। घर में दादाजी थे। उन्हें चलने में तकलीफ है। मेरे माता-पिता उन्हें लेने घर गए। दादाजी को तो उन्होंने सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन दूसरे धमाके के बाद पत्थरों की बारिश होने लगी। बड़े-बड़े पत्थर माता-पिता के सिर पर गिरे। दोनों की मौत हो चुकी है। नेहा ने कहा कि हम अनाथ हो गए। रहने को घर भी नहीं बचा। माता-पिता की अर्थी भी दूसरों के घर से उठाना पड़ी।'

फोन कर बिजली बंद कराई, नहीं तो करंट से लोग मरते

फैक्टरी के पास की बस्ती में बिजली विभाग में काम करने वाले कर्मचारी इशहाक खान भी रहते हैं। वे हादसे के वक्त घर के पास थे। उन्होंने कहा, 'धमाके के बाद बिजली के पोल झुक गए। तार जमीन तक आ गए थे। मैंने तत्काल फोन लगाकर बिजली सप्लाई बंद कराई, नहीं तो भगदड़ के दौरान लोग बिजली के तारों के करंट से भी मरते।'

पत्थरों की बरसात हो रही थी

प्रत्यक्षदर्शी लोकेश कलम ने बताया- 'धमाके के बाद पत्थरों की बरसात हो रही थी। ज्यादातर लोग पत्थर लगने से घायल हुए है। खेतों में शवों के टुकड़े थे। एक बच्ची का हाथ कंधे से अलग हो गया था। फैक्ट्री की लोहे की छत के नुकिले टुकड़े दूर-दूर तक उड़े। आसपास के खेतों मे लगे पेड़ और फसलें तक जल गई।'

कृषि भूमि पर बिना लाइसेंस थी फैक्ट्री, बच्चों से बंधवाते थे सुतली, कलेक्टर-एसपी हटाए

अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद मलने में शवों की तलाश का ऑपरेशन 24 घंटे चला। मलने में कोई नया शव नहीं मिला। बुधवार रात तक हादसे में हताहतों की संख्या 11 ही रही। फॉरेंसिक टीम ने भी जांच को और सैंपल कलेक्ट किए। एफएसएल डायरेक्टर शशिकांत शुक्ला के अनुसार, जांच में मानव अंग नही मिले हैं। एक ब्लड स्टैन मिला है। मंगलवार को एक शव झुलसा हुआ था। शिनाख्त डीएनए जांच के बाद होगी। धमाके की पड़ताल के लिए टीम मौके पर पहुंची तो सामने आया कि हरदा में राजेंद्र और सोमेंद्र की पटाखा फैक्ट्री कृषि भूमि पर चल रही थी। इसके लाइसेंस भी नहीं थे। केवल भंडारण की मंजूरी थी। इसकी आड़ में खतरनाक बारूद से सुतली बम बनाने का काम चल रहा था। फैक्ट्री के एक हिस्से पर कामर्शियल उपयोग को मंजूरी थी. बाकी कृषि भूमि थी। 15-15 किलो तक के विस्फोटक रखने के दो लाइसेंस थे, लेकिन वे भी निरस्त थे। फैक्ट्री में 3 से 12 साल के मासूमों से सुतली बम बंधवाने का खतरनाक काम कराया जाता था। बारूद स्टोरेज के लिए बेसमेंट बनाया गया था।

कारखाना निरीक्षक सस्पेंड

मंत्री को नहीं बता पाए एसपी कि आरोपी कहां है, गवाही देने सबूत के साथ कोर्ट नहीं गए अफसर

हादसे के एक दिन बाद ही सरकार ने कलेक्टर ऋषि गर्ग और एसपी संजीव कुमार कंचन को हटा दिया। बुधवार को सीएम डॉ. मोहन यादव घटनास्थल पर पहुंचे और जायजा लिया, इसके तुरंत बाद आदेश जारी हो गए। दरअसल, मंगलवार को स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदयप्रताप सिंह ने मौके पर एसपी कंचन से पूछा था कि आरोपी कारोबारी कहां है, उससे पूछताछ की? एसपी ने जानकारी नहीं होने की बात की। तुरंत एसपी आरोपी के घर पहुंचे। वहां ताला मिला। मंत्री नाराज हुए तो कुछ घंटे बाद आरोपी धरा गया।

सरस्वति महाभागे विद्ये कमललोचने । विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमोऽस्तुते ॥

बसंत पंचमी

के दिन घर ले आएं ये चीजें

मां सरस्वती के साथ देवी लक्ष्मी भी होगी प्रसन्न

प्रत्येक वर्ष माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है. इस बार यह त्योहार 14 फरवरी को है. सनातन धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व होता है। लोग इस दिन को अलग-अलग अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं. धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, इस तिथि पर कुछ विशेष चीजों को खरीदकर घर लाने से देवी सरस्वती की खास कृपा प्राप्त की जा सकती है. आइए आपको बताते हैं इस दिन कौन सी चीजें घर लानी चाहिए.

गेंदे के फूल

बसंत पंचमी पर बसंती रंग का विशेष महत्व होता है. ऐसे में यदि आप भी अपने घर में गेंदे का पौधा लगा सकती है. फ्लावर पॉट में पीले फूल लगा सकते हैं. घर को इन फूलों से सजा सकती हैं. आप अपने मन के मुताबिक, तोरण की डिजाइन बना सकती हैं

वीणा

वीणा देवी सरस्वती की सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक है. वीणा को बहुत पवित्र माना जाता है तथा इसे घर में रखने से सुख-शांति का माहौल बना रहता है.

वाद्य यंत्र

संगीत में रुचि रखने वाले लोगों को बसंत पंचमी के दिन बांसुरी-वीणा या वाद्य यंत्र घर लाना चाहिए. ऐसा करने से मां देवी सरस्वती खुश होती हैं.

वैवाहिक जीवन

सरस्वती पूजा के दिन शादी का जोड़ा या गहने खरीदना खास फलदायी होता है. ऐसे करने से आने वाला वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है.

घर लाएं ये पौधा

बसंत पंचमी के दिन घर में मोरपंखी का पौधा लाना बहुत शुभ होता है. आप इस पौधे को घर की पूर्व दिशा में रख सकते हैं. ड्राइंग रूम या घर के मुख्य द्वार पर भी लगा सकते हैं.

सरस्वती प्रतिमा या तस्वीर लाएं

बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की कृपा के लिए बच्चों के कमरे में उनकी फोटो या प्रतिमा लगाएं. ऐसा करने से विद्यार्थियों में पाठ के प्रति रुचि पैदा होती है.

मोर पंखी का पौधा

बसंत पंचमी के दिन घर में मोर पंखी का पौधा लाना अच्छा होता है. मोरपंखी के पौधे को विद्या का पौधा माना जाता है. ऐसी परम्परा है कि इसे लगाने से घर के बच्चों पर माता सरस्वती का आशीर्वाद बना रहता है.

बसंत पंचमी पर राशि अनुसार करें मंत्रों का जाप, किसी काम में नहीं आएगी बाधा

सनातन धर्म में माता सरस्वती को ज्ञान और बुद्धि की देवी के रूप में पूजा जाता है। वहीं बसंत पंचमी का दिन देवी सरस्वती की पूजा-अर्चना के लिए समर्पित माना जाता है। ऐसे में आप इस शुभ दिन पर अपनी राशि के अनुसार मां सरस्वती के मंत्रों का जाप करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं।

• **मेष राशि :** बसंत पंचमी के दिन सफेद रंग के वस्त्र धारण कर सरस्वती मां की पूजा करें और सरस्वती कवच पाठ करें। इसके साथ ही ॐ वाग्देवी वागीश्वरी नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से मां सरस्वती प्रसन्न होती हैं और साधक को ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं।

• **वृषभ राशि :** वृषभ राशि के जातकों को बसंत पंचमी के दिन पूजा के दौरान माता को सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इसके बाद माता को फूल अर्पित करें और ओम कौमुदी ज्ञानदायिनी नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से व्यक्ति के ज्ञान में बढ़ोतरी होती है।

• **मिथुन राशि :** मिथुन राशि के जातकों को मां सरस्वती की पूजा के दौरान उन्हे पेन (कलम) अर्पित करें करना चाहिए। इसके साथ ही ॐ माँ भुवनेश्वरी सरस्वत्यै नमः मंत्र का जाप करें।

• **कर्क राशि :** कर्क राशि वाले जातकों को बसंत पंचमी के दिन ॐ माँ चन्द्रिका देव्यै नमः का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही मां सरस्वती को खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से छात्रों को विशेष लाभ देखने को मिल सकता है।

• **सिंह राशि :** सिंह राशि के लोगों को मां सरस्वती की पूजा के दौरान ओम मां कमलहास विकासिनी नमः मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में विशेष लाभ देखने को मिल सकता है।

• **कन्या राशि :** कन्या राशि वाले बसंत पंचमी के दिन ॐ मां प्रणवनाद विकासिनी नमः मंत्र का जाप करें और गरीब बच्चों में पढ़ाई से संबंधित सामग्री जैसे जिसमें पेन, पेंसिल किताबें आदि बांटे। इस उपाय को करने से पढ़ाई में आ रही आपकी बाधा दूर हो सकती है।

• **तुला राशि :** तुला राशि वाले लोग सरस्वती पूजा के दौरान ओम मां हंस वाहिनी नमः मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही किसी ब्राह्मण को सफेद रंग के वस्त्र दान करें। ऐसा करने से छात्र जीवन में सफलता मिलती है।

• **वृश्चिक राशि :** वृश्चिक राशि के जातकों को सरस्वती पूजा के दिन ॐ शारदै देव्यै चंद्रकांति नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही मां सरस्वती की पूजा के बाद उन्हें लाल रंग का पेन उन्हें अर्पित करें।

• **धनु राशि :** धनु राशि वाले लोग मां सरस्वती को पीले रंग की कोई मिठाई अर्पित करें और ॐ जगती वीणावादिनी नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से साधक की एकाग्रता में वृद्धि होती है।

• **मकर राशि :** मकर राशि वाले जातक सरस्वती पूजा के दिन ओम बुद्धिदात्री सुधा मूर्ति नमः मंत्र का जाप करें। साथ ही इस दिन निर्धन व्यक्ति को सफेद रंग का अनाज जैसे चावल आदि दान करें। ऐसा करने से मां सरस्वती बल और बुद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें।

• **कुंभ राशि :** कुंभ राशि के लोगों को बसंत पंचमी के दिन ॐ ज्ञानप्रकाशिनी ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का जप करने से विशेष लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही गरीब बच्चों में पढ़ाई से संबंधित चीजों का दान करें। ऐसा करने से मां सरस्वती की कृपा से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

• **मीन राशि :** मीन राशि वालों को सरस्वती जी की कृपा प्राप्ति के लिए पूजा के दौरान ओम वरदायिनी मां भारती नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन कन्याओं में पीले रंग के कपड़े दान करें। ऐसा करने से आपकी करियर संबंधी बाधाएं दूर होंगी।

कैसे करें बसंत पंचमी पर पूजा और भोग की तैयारी

मां सरस्वती की पूजा में पीले रंग का बहुत महत्व माना जाता है। इस दिन शुभ रंग पीला ही होता है। सरस्वती मां पर पीले रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना साज सज्जा करना भी शुभ माना जाता है। आप बसंत पंचमी के दिन सुबह उठकर स्नान कर अपने आप को साफ सुथरा करें और पीले या सफेद रंग के वस्त्र को धारण करें। इसके बाद चौकी पर पीले रंग के वस्त्र को बेछाकर मां सरस्वती की प्रतिमा की सजावट करें। मां के समक्ष अक्षत, आम के फूल और पीले रंग की रोली वे चंदन आदि अर्पित करें अथवा पूजा सामग्री का इस्तेमाल करें।

- **इसके साथ ही वसंत पंचमी पर मां सरस्वती के लिए खास भोग भी तैयार किया जाता है। मां सरस्वती को केसर की पीली खीर भोग में लगाई जाती है।**
- **इसके साथ ही चने की दाल के हलवे का भोग भी बेहद अच्छा माना जाता है।**
- **इस दिन मां को सूजी के पीले रंग का हलवा भी भोग में लगाया जाता है।**
- **इसके साथ ही बेसन या बूंदी के लड्डू भी भोग में रखे जाते हैं।**
- **भोग में पीले रंग के चावल भी अच्छे माने जाते हैं।**
- **आखिर में भोग में रबड़ी भी रखी जाती है जो केसर के पीले रंग से सजी हो।**

बसंत पंचमी पर बच्चों से जरूर करवाएं ये 5 काम, करियर में मिलेगी तरक्की

प्रत्येक वर्ष माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है. इस बार यह त्योहार 14 फरवरी को है. सनातन धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व होता है। लोग इस दिन को अलग-अलग अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं. यह दिन छात्रों के लिए बेहद ही विशेष होता है क्योंकि इस दिन को शिक्षा की शुरुआत करने और पढ़ाई में कामयाबी का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत विशेष माना जाता है. इस दिन देवी सरस्वती की पूजा के साथ ही व्रत भी किया जाता है तथा पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं.

धार्मिक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन देवी शारदा की आराधना करने से कला, संगीत और शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी प्राप्त होती है. ऐसा कहा जाता है कि इस दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई थीं इसलिए इस दिन को उनके जन्मदिवस के तौर पर भी मनाया जाता है. शास्त्रों के मुताबिक, बसंत पंचमी के दिन बच्चों-छात्रों द्वारा कराए गए कुछ उपायों से देवी सरस्वती की कृपा उनपर जीवन भर बनी रहती है तथा उन्हें हर क्षेत्र में सफलता हासिल होती है.

लक्ष्य पर फोकस करने के लिए –

यदि आपका बच्चा अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तथा तो इसके लिए मां सरस्वती की तस्वीर स्टडी टेबल के पास रख दें. कहा जाता है कि ऐसा करने से उनका पढ़ाई में मन लगेगा एवं साथ ही याद्दाश्त भी अच्छी होती है.

ऐसे कराएं बच्चों से पूजा –

यदि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तथा उसका ध्यान पढ़ाई से बार-बार भटकता है, तो ऐसे में अपने बच्चे से देवी सरस्वती की पूजा कराएं. बच्चे के हाथों से पीले फल, फूल, केसर के पीले चावल मां सरस्वती को चढ़ाएं. इससे देवी प्रसन्न होती हैं तथा आपके बच्चे के मानसिक विकास का आशीर्वाद देती हैं.

इस काम से मिलेगी तरक्की –

जिन बच्चों को क्लास में बोलने में समस्या हो या फिर वे पढ़ने के बाद भी सही तरीके से लिख नहीं पाते हैं, तो इसके लिए बसंत पंचमी पर चांदी की कलम को शहद में डूबोकर बच्चे की जीभ पर ऊं लिखें. ऐसी मान्यता है इससे बोलने में आ रही समस्या दूर होती है तथा संतान पढ़ाई में आगे रहती है.

पढ़ाई में आ रही रुकावट के लिए –

जिन छात्रों की पढ़ाई में अड़चन आ रही है, तो उनसे बसंत पंचमी पर मां सरस्वती को सफेद चंदन अर्पित कराएं तथा फिर 'ॐ ऐं सरस्वत्यै ऐं नमः' मंत्र का 108 बार जाप कराएं. मान्यता है इससे पढ़ाई में कामयाबी प्राप्त होती है.

याद करने की शक्ति होगी तेज –

बसंत पंचमी पर बच्चों के हाथों जरुरतमंदों को किताबें एवं पेन दान कराएं. मान्यता है कि ऐसा करने से वाणी दोष दूर होता है एवं बच्चे की याद करने की शक्ति तेज होती है. बच्चों का मन आध्यात्म की तरफ अग्रसर कराने के लिए किताबें एवं पेन देवी सरस्वती के चरणों में चढ़ाएं.

काव्य कोष के झरोखों से

बसंत का आगमन

शिशिर के बाद बसंत ऋतु का आगमन 14 फरवरी 2024 को प्रारंभ हो रहा है। वह ऋतुओं में सर्वाधिक महत्व इस ऋतु को साहित्य से लेकर स्वास्थ्य सेवा के लिये एवं जड़ और चेतन को स्फूर्तिदायक और मनमोहक माना गया है। प्रकृति के चितेरे कवियों ने ऋतुओं को अपनी अंतर आत्मा की अनन्त गहराईयों से जो अनुभव किया उसे साहित्य में स्थान देकर वे अमर हो गये और उनकी रचनाएं कालजयी बन गई।

पूस की रातें शिशिर के सानिध्य में हाड़ कंपाने वाली होती है। शिशिर की ठिठुरन भरी रातें और दिन की अनुभूति पर प्रकृति के चितेरे कवि सेनापति अपने कवित में लिखते है-

"शिशिर में ससि को सरुप पते सविताऊ।
धाम हूं मैं चांदनी की दुति दमकति है॥

शिशिर ऋतु में प्रातःकालीन धूप में भी रात्री की चांदनी की शितलता अनुभव होती है। वहीं शिशिर शनैः-शनैः अपनी शितलता को समेटकर अस्तांचल की ओर जा रहा है। अब प्रकृति की पुण्य धरा पर बसन्त का मदमाता मौसम हर्ष और उल्लास के साथ प्रकृति और मानव मन को उदीपन में प्रफुल्लित करने आ रहा है। प्रकृति के सांकेतिक कवि पदमाकर ने बसंत की आहट की हो मनमोहक छवि साहित्य में प्रस्तुत की वह बेजोड़ हृदय अनुभूति करने वाली रचना है।

विथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में
बनन में बागन में बगरो बसन्त है॥

बसंत के आते ही आम के पेड़ों पर आम्रमंज्जरी अपनी खुशबू से मानव मन को आकर्षित करती है। लताओं में वनों में बाग-बगिचों में सर्वत्र लाल-लाल टेसू के खिले हुए फूल बरबस राहगिरों को अपनी ओर खींच लेते हैं। यही तो प्रकृति के सांकेतिक परिवर्तन का मनमोहक चित्रण है। नाना प्रकार के फूल मौसम में प्रकृति को सजाने स्वयं खिल जाते हैं।

सेनापति माधव महिना में पलास तरु।
देखि-देखि माहू कविता के मन आए है॥

सेनापति कवि कहते है कि माघ के महिने पलास के फूल देख-देखकर कवि के मन में कविता कामिनी कल-कल करने लगती है। इसी महिने की शुक्ल पक्ष की बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। यही वही पुण्य स्मरणीय देवी है, जिसके कारण ज्ञान-विज्ञान अनुसंधान संभव है। ज्ञान की यह देवी मानव जाति की विकास और विश्वास की आराध्य देवी है। जिसके बगैर मानव जीवन संभव नहीं। यह देवी संसार के सार को समझने में मानव की सहायता करती है। जिस पर इसकी कृपा हो जाती है, वह भाग्यशाली सभी के हृदयों पर राज कर सकता है। बसंत पंचमी के दिन ही प्रातःकाल नवजान संतान को इसी देवी सरस्वती के दर्शन-पूजन-अर्चन कराना चाहिए। माथे पर पीला केसरिया तिलक गुड़, दही, शहद खिलाना चाहिए।

चांदी की चम्मच से शहद खिलाने से नवजात की वाणी मुखर एवं सरस होती है, जिसके कारण वह संवाद करने में सक्षम हो जाता है। बसंत पंचमी के दिन प्रायः सभी पीले वस्त्र धारण कर आपस से धनिया, गुड़ का भोग लगाकर परस्पर बांटते है। यह शुभ कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त पर जिन सौभाग्यशाली लोगों के विवाह यज्ञोपवीत, गृहप्रवेश चूड़ाकर्म संस्कार आदि होते है। वे निश्चित ही जीवन में अनन्त सुख भोगकर दीर्घजीवी भी होते है।

बसंत ऋतु का यह माह कृषि कार्य के लिए भी उत्तम माना जाता है। गेहूं की बालियां निकलने लगती है। इन्हीं नवकोपलयुक्त बालियों को होली में सेककर भोग लगाया जाता है। भारत के सुदूर उत्तर हिमालय स्थित उत्तराखंड की पावन नदियों के संगम पर मेले लगते है। परस्पर लोग एक-दूसरे की संस्कृति से संवाद कर अपनी लोकसंस्कृति के लोकाचार परम्परागत गीत-संगीत लोकगीत, लोकनृत्यों से इस बसंत को द्विगुणित कर देते है। निश्चित ही बसंत ऋतु प्राणी मात्र से लेकर वनस्पति के पल्लवित पुष्पिन होने की ऋतु है। इसीलिये इस ऋतु को ऋतु-राज भी कहा जाता है। बसंत ऋतु ही लोक जीवन को जीवित रखता है। लोकजीवन ही मानव मन पर सदा प्रसन्नता, उमंग, आशा का संचार करती है।

आ गये बसंत ऋतुराज!

आह! अनायास ही
नींद खुली पतझर की!
भूलकर सभी द्वंद्व
विहंसने लगे विहग वृंद!
मुदित होकर आ
गये हैं बसंत ऋतुराज!
लिये हुए अपने अंतस में
अनंत अभिसार!
कली - कली मुसकराने लगी
सुन भौंरों की मादक मनुहार!
रंग -रस पूरित हुए टेसू के फूल!
गुड़हल को देख कनेर ने
ओढ़ लिये हरित दुकूल!
पीताभ होकर फूल रही है सरसों !
कह रही है मैं कैसी थी परसों?
उस पर बसंत हो गया मौन!
कह रहा है - मैं हूं कौन?

✍ जगदीश प्रसाद तिवारी

बसन्त पंचमी पर विशेष

हौले-हौले बसंत आ रहा है

कायनात का जर्रा-जर्रा, झूमता नजर आ रहा है।
खुशियां मनाओ, हौले-हौले वसंत आ रहा है॥

मौसम की करवट से, कली-कली खेलने लगी।
हृदय-छुअन को आतुर, वसंत आ रहा है ॥

बाग-बगीचों की अदा, निखरी-निखरी सी है ।
फूलों पर मंडराते भंवरों के संग वसंत आ रहा है॥

मस्ताने मौसम में, सम्मोहन सा नजर आता है ।
उमंग-उल्लास-फाग के संग, वसंत आ रहा है॥

कली-कली खिल जाती है, चंग-रंग के संग ।
मन को तरंगित करने को, वसंत आ रहा है ॥

पीली-पीली सरसों, पीले-पीले ही परिधान ।
कुदरत को सुरमय करता, बसंत आ रहा है ॥

सृजनशील-पर्यावरण, वसंत की सुषमा वन।
मां - सरस्वती का प्रतीक बनने, वसंत आ रहा है ॥

साप्ताहिक समय माया

क्या सब बढ़ रहे हैं विश्व युद्ध की तरफ

पेज 1 का शेष

अमेरिका की ओर से शुक्रवार के दिन सीरिया और इराक़ में 85 लक्ष्यों पर हमले किए गए. उसकी ओर से यह पलटवार अमेरिकी सैनिक अड्डे पर ख़तरनाक ड्रोन हमले के बाद किया गया है. ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शैप्स ने कहा है कि हाल के हमले के बाद कहा कि लाल सागर में हूती विद्रोही मनमानी नहीं कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि यह हमला सुरक्षा के लिए है न कि तनाव बढ़ाने के लिए. यमन के हूती विद्रोहियों ने नवंबर में लाल सागर में व्यापारिक समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था, जिससे अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी. हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है.

शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर का इस्तेमाल बंद कर दिया है. यहाँ से आमतौर पर लगभग 15 फ़ीसद अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार होता है. ये शिपिंग कंपनियां अब लाल सागर के बदले दक्षिण अफ़्रीका के आसपास एक लंबे रास्ते का इस्तेमाल कर रही हैं.

ईरान ने अमेरिकी हमले को बताया 'रणनीतिक ग़लती', क्या मध्य पूर्व में बढ़ेगा तनाव

ईरान ने सीरिया और इराक़ में हुए अमेरिकी हमलों को 'रणनीतिक ग़लती' बताया है. अमेरिका ने ईरान से जुड़े मिलिशिया ग्रुपों के कई ठिकानों को शुक्रवार को निशाना बनाया था. जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे 'टॉवर 22' पर 28 जनवरी को ड्रोन हमला हुआ था जिसें तीन अमेरिकी सैनिक मारे गए. अमेरिका ने इसे लेकर ही जवाबी हमले किए हैं. व्हाइट हाउस ने इस ड्रोन हमले के लिए 'ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप को ज़िम्मेदार ठहराया' था.

ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीरिया और इराक़ पर किए गए हमलों से 'इलाक़े में तनाव और अस्थिरता बढ़ने के अलावा और कोई नतीजा नहीं निकलेगा.' इससे पहले, इराक़ ने भी कहा था अमेरिका के हमले इस क्षेत्र में 'विनाशकारी परिणाम' लेकर आएंगे.

हूती विद्रोहियों ने क्या अमेरिकी गठबंधन को ऐसे युद्ध में फंसा दिया है जिसे वो जीत नहीं सकते?

यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों को नष्ट करने की कोशिश करने वाली अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और हॉलैंड की अंतरराष्ट्रीय टास्क फ़ोर्स के लिए जीत हासिल करना आसान काम नहीं है. कथित तौर पर ईरान से समर्थन हासिल करने वाले हूती विद्रोही नवंबर के मध्य से लेकर अब तक लाल सागर में अंतरराष्ट्रीय और व्यापारिक जहाज़ों पर तीस से अधिक हमले कर चुके हैं. इन हमलों के ख़त्म होने के कोई आसार भी नज़र नहीं आते. 23 जनवरी को संवाददाताओं से बातचीत में अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने कहा कि वो लाल सागर और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा तय करने और इन हमलों का जवाब देने के लिए कुछ और उपाय करने को तैयार हैं. इन हमलों से समुद्री आवाजाही से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय उद्योग प्रभावित हुआ है और इस आशंका को भी बढ़ावा मिला है कि इसराइल और हमास के युद्ध के कारण मध्य पूर्व अस्थिर हो सकता है. क्या अमेरिका और उसके सहयोगी एक ऐसे समूह के ख़िलाफ़ जीत हासिल कर सकते हैं जिनके ख़िलाफ़ सऊदी अरब लगभग एक दशक तक लड़ता रहा, लेकिन नाकाम रहा?

'अमेरिका और ब्रिटेन के पास नहीं था कोई विकल्प'

इन हमलों से पहले राजनयिक कोशिशों से लाल सागर में स्थिति को बेहतर करने की कोशिश की गई लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल सकी.

यमन के लिए अमेरिका के विशेष दूत टिम लैंडरकिंग का कहना है कि यह अफ़सोस की बात है कि स्थिति इस मोड़ पर पहुंच गई है.

यमन के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों पर क़ब्ज़ा किये हूती विद्रोहियों का कहना है कि उनके हमले फ़लस्तीनियों के साथ एकजुटता जताने के लिए है क्योंकि इसराइल ने ग़ज़ा पर हमला किया है.

थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल के विलियम वेच्सलर का मानना है कि अमेरिका और ब्रिटेन के पास ताक़त का इस्तेमाल करते हुए जवाब देने के अलावा और कोई चारा नहीं था.

वह कहते हैं, 'अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आठ प्रमुख समुद्री चौकियां हैं, जिनमें से आधी मध्य पूर्व में हैं. इसके अलावा मध्य पूर्व ऊर्जा की ज़रूरतें पूरी करने वाला दुनिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है. हूती विद्रोहियों ने उन समुद्री चौकियों में से एक को सीधी धमकी दी जो बेहद असामान्य है.' 'जो व्यक्ति भी इस बात को समझता है कि हमारे दैनिक जीवन को बेहतर बनाने में ऊर्जा की भूमिका क्या है, जिस किसी को भी आर्थिक प्रगति की परवाह है, उसे उन महत्वपूर्ण चौकियों की सुरक्षा का महत्व समझना होगा.'

यूपीए और एनडीए में किसकी आर्थिक नीतियां बेहतर?

पेज 1 का शेष

दूसरी तरफ़ बीजेपी ने बैड बैंक लोन में उछाल, बजट घाटे से भागना, कोयला से लेकर 2जी स्पेक्ट्रम तक हर चीज़ के आवंटन में घोटालों की एक श्रृंखला और फैसला लेने में अक्षमता जैसे कई आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं. बीजेपी का कहना है कि इसकी वजह से देश में निवेश की गति धीमी हुई है.

विभिन्न विश्लेषणों से शायद ये पता चले कि दोनों ही पार्टियां एक-दूसरे के बारे में जो दावे कर रही हैं, कुछ हद तक वो सही बातें भी हैं.

ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन के मिहिर शर्मा कहते हैं, 'दोनों ओर के आरोपों में कुछ सच्चाई है. दोनों ने बुरे फ़ैसले लिए, कांग्रेस ने टेलीकॉम और कोयला में और बीजेपी ने नोटबंदी में.'

लेकिन यूपीए बनाम एनडीए के 10 वर्षों के तुलनात्मक आर्थिक आंकड़ों पर एक नज़र डालने से दोनों के प्रदर्शन की मिली-जुली तस्वीर सामने आती है.

लेकिन सच ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर वैश्विक आर्थिक संकट के मुक़ाबले कोविड महामारी के कहर का असर अधिक था. इसलिए ताज्जुब नहीं कि एनडीए सरकार के दौरान एक दशक का जीडीपी औसत कम रहा.

स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की पूर्व अर्थशास्त्री बृंदा जागीरदार ने कहा, 'कोविड ने अर्थव्यवस्था के सामने जो बाधा पैदा की वो बहुत बड़ी थी. इस महामारी ने इस दशक के दौरान कुछ सालों के लिए अर्थव्यवस्था की गति को धीमा कर दिया.' लेकिन बृंदा जागीरदार ने कहा कि इस सरकार ने बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने और अन्य चीज़ों के अलावा अंतिम पायदान तक प्रशासन में सुधार करके आने वाले सालों में 'तेज़ी से विकास' की नींव रखी है.

क़ीमतें बढ़ने के मामले में मोदी सरकार का प्रदर्शन बेहतर रहा

लेकिन मिहिर शर्मा का कहना है कि बीजेपी का रिकॉर्ड बेहतर दिखता है क्योंकि इसके अधिकांश कार्यकाल में तेल की क़ीमतें कम रहीं, जबकि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान इसी वजह से महंगाई और बजट घाटा अधिक था.

मोदी सरकार ने सड़क निर्माण जैसे पूंजीगत व्यय पर अधिक खर्च़ किया

एनडीए के शासनकाल में जीडीपी में मैन्युफ़ैक्चरिंग सेक्टर का जो हिस्सा होता है उसमें कमी आई है. विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार जिन 10 सालों में यूपीए सरकार सत्ता में थी, उन सालों में मैन्यूफ़ैक्चरिंग सेक्टर का औसत 15 से 17 फ़ीसदी के बीच था. वहीं मोदी सरकार के कार्यकाल में 'मेक इन इंडिया' जैसी मुहिम और उत्पादन से जुड़ी छूट पर अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद, 2022 के लिए उपलब्ध ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मैन्युफ़ैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में हिस्सा गिरकर 13 फ़ीसदी आ गया.

निर्यात में वृद्धि दर एनडीए के मुक़ाबले यूपीए के दौरान तेज़ थी

ये दोनों ही कई कारकों की वजह से हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण और फ़ैक्ट्रियों के लिए पर्यावरण की मंज़ूरी मिलने में मुश्किलें. साथ ही एक सच्चाई ये भी है कि भारत उस तरह वैश्विक व्यापार से नहीं जुड़ा है जैसा उसे होना चाहिए.

लंबे समय से ये कारक देश के मैन्युफ़ैक्चरिंग और निर्यात वृद्धि को कम रखने का कारण रहे हैं.

मानव विकास सूचकांक पर प्रदर्शन

मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के मामले में भी एनडीए का प्रदर्शन यूपीए के मुक़ाबले बुरा रहा है. यह सूचकांक, स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति, शिक्षा तक पहुंच और व्यक्ति के जीवन स्तर में प्रगति का मानक है.

2004 से 2013 के बीच भारत के एचडीआई मूल्य में 15 फ़ीसदी का सुधार हुआ.

हालांकि यूएनडीपी के ताज़ा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2014 और 2021 के बीच इसमें केवल 2 फ़ीसदी का सुधार हुआ. अगर कोविड महामारी के दो सालों को छोड़ भी दिया जाए तो भी 2019 तक एचडीआई में, यूपीए के पांच सालों के 7 फ़ीसदी के मुक़ाबले केवल 4 फ़ीसदी का सुधार रहा है.

असल में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग गिरी है. कुल 191 देशों में 2004 में भारत 131 पायदान पर था, जबकि 2021 में वो 132 पर आ गया है.

हाल ही में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने इस मामले में चिंता ज़ाहिर की थी.

उन्होंने कहा कि 'फ़िज़िकल कैपिटल' बनाने में बहुत समय खर्च किया गया लेकिन 'ह्यूमन कैपिटल' बनाने में और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया.

उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि भारत में कुपोषण सब-सहारा अफ़्रीका के कुछ हिस्सों से भी अधिक था, यह एक ऐसे देश के लिए ये 'अस्वीकार्य' है जिसकी विकास दर दुनिया के अधिकांश हिस्से को पीछे छोड़ रही है.

ऊपर की गई तुलना देश के आर्थिक विकास के क्षेत्र में बीते दो दशकों में सत्ता में रही दो अलग-अलग सरकारों के प्रदर्शन को लेकर व्यापक तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं है.

इस तरह की तुलना करते वक्त शेयर बाज़ार में रिटर्न्स, सब्सिडी पर खर्च, नए रोज़गार पैदा करने और खपत जैसे आर्थिक मानदंडों पर भी नज़र डाली जा सकती है. इस बात की पूरी संभावना है कि इससे जो तस्वीर उभरेगी वो मिली-जुली होगी, जिसमें एक सरकार किसी एक क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करती दिखेगी तो किसी दूसरे क्षेत्र में पिछड़ती दिखेगी.

आर्थिक नीति निर्धारण भी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो अलग-अलग सरकारों के बीच चलती रहती है, जिसमें सरकार को अपने पूर्ववर्ती से विरासत में अच्छे और बुरे काम मिलते हैं.

कभी-कभी एक सरकार द्वारा की गई पहल या कदम को उसके बाद आने वाली सरकार आगे बढ़ाती है और मज़बूत करती है. उदाहरण के तौर पर यूपीए की सफलता का श्रेय आधार पर आधारित पहचान पत्र व्यवस्था को जाता है जिसे 2009 में यूपीए के कार्यकाल में लाया गया था. ये सभी कारण आर्थिक मामलों में विश्लेषण को ब्लैक एंड व्हाइट तक सीमित करने की कोशिश को नाकाम साबित करते हैं. और सच यही है कि इस मामले में सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छिपी है.

कार्टून कोना

कमीशनखोरी में संविदा आउटसोर्स ठेका कर्मियों शोषण

पेज 1 का शेष

हालात यहां तक भी हैं। कि पिछले 8 सालों में लगभग 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी-अधिकारी बिना स्थाई पदोन्नति के सेवानिवृत हो गए जिससे उनको पेंशन में भी 'भारी 20 से 30% तक का घाटा उठाना पड़ रहा है क्योंकि उनकी पेंशन का निर्धारण उनके मूल पद के आधार पर मिलने वाले वेतन का आधा दिया जा रहा है।

शासकीय विभागों में काम करवाने उक्त पदों पर भर्तीयां करने की अपेक्षा, पुरानी सेवानिवृत्ति करो होने वाले कर्मियों को मोटी दलाली पर संविदा पर नियुक्ति देकर, सरकारी कार्यालयों जैसे विद्युत कंपनियां नगर निगम पालिकाएं पंचायत स्वास्थ्य लोनिवि केंद्र के रेलवे पोस्ट ऑफिस आदि में बड़े-बड़े कार्यो को संपन्न करवाने के लिए स्थाई भर्तीयां करने की अपेक्षा मोटी दलाली पर कार्य को पूरा करने के लिए वहां के अधिकारी, मंत्री नेता संचालक प्रमुख अभियंता आयुक्त सचिन प्रधान सचिव कंपनियों एजेंसीयों को ठेका दे कार्य पूरा करवाते हैं। ये एजेंसियां कंपनियां फिर उन सेवाओं को पूर्ण करने के लिए अपने स्तर पर अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन से भी कम पर नियुक्तियां देकर आवश्यकता के 100% का वेतन ले 60% कर्मचारियों से ही 8 घंटे की अपेक्षा 12 से 16 घंटे तक लिखकर भी वेतन 8 से 10, 12 तक ही देती है। जबकि सरकारी खातों में वह 12, 15 हजार से लेकर रु. 30 हजार तक प्रति माह तक का वेतन भुगतान शासकीय खर्चे में होता है।

दैनिक वेतन भोगी लोनिवि लोस्वायां, उद्यानिकी कृषि वन आदि अधिकांश विभागों में मजदूर सहायक से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर तक दैनिक वेतन भोगी के रूप में पिछले 20 से 30 सालों से कार्यरत होने के उपरांत भी उन्हें ना तो कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिया जाता है। ना स्थाई छुट्टियां महंगाई भत्ते व अन्य प्रकार की नियमित कर्मचारी के तरह की सुविधायें उन्हें मिलती है। यहां तक की 20-30 वर्ष काम करने के उपरांत भी उन्हें माह के 30 दिन का वेतन नहीं बल्कि 20 से 26 दिन का वेतन मिलता है जितनी भी सरकारी छुट्टियां पड़ती हैं। शनिवार रविवार के साथ उन सब का वेतन भी काट दिया जाता है। अब सोचिए 8 से 10000 रुपए के वेतन में भी 20 दिन का वेतन मिलेगा तो कैसे कोई दैनिक वेतन भोगी आउटसोर्स और ठेका कर्मी अपना जीवन यापन कर पाएगा और कहने को सरकारी कर्मचारी है। इतना ही नहीं आउटसोर्स और ठेका कर्मियों के बिलों के भुगतान में 28% जीएसटी भी काटा जाता है।

जबकि दैवेभो के वेतन मजदूरी का भुगतान सीधे सरकारी विभागों से किये जाने के कारण विश्व बच जाते हैं। पर अधिकांश विभागों में कंप्यूटर आपरेटर जो लगभग 3 लाख से भी ज्यादा हैं। और 20-25 वर्षों से ज्यादा समय से काम करने के बाद में भी जबकि उन्होंने सीधे फिल्म सरकारी विभागों में काम शुरू किया था। पर बाद में मोटी कमाई के चक्कर में नेता मंत्री अधिकारी की एजेंसी कंपनियों को ठेका देने का कारण आउटसोर्स कर्मचारी बना दिये जाने के कारण उल्टी ही उनका वेतन जीएसटी काटने के कारण 15-12-10 से कम कर 8-9 हजार हो गया।

अभी यह वेतन भी समय पर नहीं मिलता और जब से नई सरकार बनी है 2 महीने से आने को विभागों में इन स्थाई दैनिक वेतन भोगी ठेका संविदा कर्मियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है दूसरी तरफ मध्यस्थ आउटसोर्स ठेका एजेंसी कई बार विभाग से भुगतान लेने के बाद कर्मचारियों को महीना तक वेतन नहीं देती और उसे धन का उपयोग अन्य आने को स्थान पर कर लिया जाता है इससे लाखों ठेका कर्मी न्यूनतम जीवन यापन करने में भी परेशान हो जाते हैं इस पर भी यह हरामखोर भारतीय प्रताड़ना सेवा जोहर विभाग में प्रधान सचिव सचिव से लेकर नीचे तक के सारे विभागाध्यक्षों से लेकर जिन अधिकारियों के अधीनस्थ वे काम कर रहे होते हैं। ऐसे कर्मचारियों का भरपूर सामाजिक आर्थिक यौन शोषण करने के उपरांत भी उन्हें बात-बात में हटाने की धमकी दिया करते हैं। शोषित कर्मचारी जीवन यापन और परिवार की आवश्यकताओं को देखते हुए चुपचाप आंसू बहाते हुए पशुओं की भांति काम करने के लिए मजबूर रहते हैं।

आखिर देश की यह लोकतांत्रिक सरकार हर कदम जनता के साथ अपने ही अधिकारियों कर्मचारियों का शोषण कर तांत्रिक क्यों हो गई जबकि सरकार इन कर्मचारियों-अधिकारियों को वेतन कोई अपनी जेब से नहीं जनता से भय के दम पर लूटे गए करो से ही देती है और यदि सरकार उन्हें नियमित वेतनमान देना शुरू भी कर देगी तो उन देश के करोड़ों कर्मचारियों द्वारा मेहनत के बदले में प्राप्त निर्मित कर्मचारियों की तरह वेतन प्राप्त होने पर भी या तो वह कर्मचारी अपने व परिवार के भरण पोषण के लिए बाजार में खर्च करेगा तो भी सरकार को हर खरीदी परन केवल कर मिलेगा वर्णन अधिकतम पैसा बाजार में चलन में रहने के कारण उससे करोड़ों लोगों को रोजी रोजगार भी मिलेगा या वह कर्मचारी बचे हुए धन को बैंक में रखेगा जिसका भी सरकार भरपूर दोहन करेगी। तो सरकार को चाहिए कि देश की आर्थिक समृद्धि के लिए कम से कम सरकारी खजाने से तो अपने ही कर्मचारियों-अधिकारियों के शोषण की अपेक्षा नियमित भारतीय कर भरपूर वेतन दें ताकि उनकी तरह शक्ति बढ़े और देश की आर्थिक समृद्धि में भी काम आए।

बहुराष्ट्रीय कं. की मिलावट अमृत, छोटे व्यापारियों की विष

छोटे उद्योगों व्यापारियों के संघों को करना चाहिए आंदोलन

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से कलेक्टर तक मोती वसूली के लिए तोड़फोड़ कर तांडव

पूरा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 यथार्थ में बहुराष्ट्रीय कंपनी के इशारे परउनके मोटे फायदे छोटे व्यापारियों उद्योगों विक्रेताओं को खत्म करने का हिस्सा है यह पिछले18 सालों से सामने आ रहा है क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी और बड़ी शॉपिंग मॉल खाद्य सुरक्षा अधिकारी से लेकर कलेक्टर कमिश्नर प्रधान सचिव मुख्य सचिव मुख्यमंत्री तक को धन बनते हैं इसलिए उनके इशारे पर छोटे व्यापारियों विक्रेता उद्योगों को नष्ट करने का षड़यंत्र किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा वह मानक अधिनियम 2006 में किसी भी खाद्य वस्तु कोसंदेश पड़ पाए जाने पर उसके नमूने लेने की व्यवस्था की गई है पर उन नमूने लेने की आड़ में घोर भ्रष्ट जालसाज मनीष स्वामी जो पहले भी अपने भ्रष्टाचार के चलते सस्पेंड किया जा चुका है पुणे मोटा पैसा खर्च कर इंदौर लौट आया है।

जनता को चाहिए की सबसे पहले अमूल सांची दूध के साथ शॉपिंग मॉल में रखें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पैकेज्ड फूड जिसमें आटे से लेकर सभी प्रकार के तैयार किए हुए खाद्य पदार्थों की शिकायत कर जांच करवायें। की शिकायत करें फिर देखें इनकी औकात है कि उनकी जांच करते हैं, कि नहीं। अमूल और सांची जो दूध पैक कर रहे हैं जब इतने जानवर नहीं तो लाखों लीटर आयातित पाउडर का बना दूध 64, 66 रुपए के भाव में ताजा दूध लिख उसमें बटर ऑयल मिलाकर जो फेट मिलाई जा रही है। उसके नमूने ही जांच कर जनता को रिपोर्ट दें।

यह सारा षड़यंत्र बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माल की बिक्री बढ़ाने जो इन्हें महीना बांटते हैं। और छोटे व्यापारियों को खत्म करने का है। बाजार में रंग किए हुए फ्रोजेन मटर, सभी प्रकार के पैकेज्ड मसाले, चॉकलेट बिस्किट सभी शीतल पेय जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पैकेजिंग का है। बिक रहे हैं। उनके भी नमूने नहीं लिए उनकी दुकान नहीं तोड़ी उनकी फैक्ट्रियां नहीं तोड़ी। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शॉपिंग मॉल में बिकने वाला आटा तक जहरीला है। जिसमें कीटनाशक व सफेदी बनाये रखने घातक रसायन मिलाते जाते हैं। जो चर्म रोग उत्पन्न करने से लेकर घातक लिवर किडनी ह्दय तक की बीमारियां दे रही है। जिसे भारत शासन का स्वास्थ्य मंत्रालय का खाद्य एवं औषधि नियंत्रक मानता है कि 96.4% पैकेज्ड फूड घातक बीमारियां बांटते हैं।

कभी मोदी के मित्र बाबा रामदेव के खाद्य वस्तुओं के औषधीयों के नमूने लिए क्या?

फिर जब ईडी सीबीआई मुख्यमंत्री के घर पर छापे मार सकता हैजो जिलों के सबसे बड़े डकैत कलेक्टर एसपी के भी फोन रिकॉर्ड करके उनके घरों पर भी छापे मारे सो 200 करोड़ का कैश उनके यहां भी मिल जाएगा। जिन्हें उन्हें मासिक चंदे के रूप में मुख्यमंत्री को पहुंचाना पड़ता है।

फिर मनीष स्वामी तोपहले भी कई बार लूट डकैती और भ्रष्टाचार में सस्पेंड हो चुका हैअब नए कलेक्टर के साथ मिलकर मोटी कमाई करने के लिए सौंफ का सैंपल लेकर बिना प्रयोगशाला में भेजे फैक्ट्री तोड़ देने का कौन सा कानून है?

व्यापारियों को चाहिए कि एकत्रित होकर इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई जिसे पहले आलू की फैक्ट्री के बारे में खराब आलू कहकर फैक्ट्री तुड़वा थी। उसे पर याचिका लगाने के बादउच्च न्यायालय नेयही निर्देश दिया था कि आपका काम नमूना लेने का है आप नमुना लीजिए।आप ना तो कोई शासन द्वारा नियुक्त वैज्ञानिक या विश्लेषक हैं। उसके लिए सरकारी प्रयोगशालाएं हैं। ना कोई दिव्य ज्ञानी जो आप देखते ही उस मिलावट का पता लगाकर मोटी वसूली करने के लिए फैक्ट्री तोड़ देते हैं। और इस काम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वामी मास्टर है।

सभी उद्योगपतियों व्यापारियों छोटे विक्रेताओं को चाहिए कि वह एकत्रित हो कर इनके बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बिक्री बढ़ाने के षडयंत्रों के खिलाफ सड़कों पर उतरे और उनकी शिकायतें करें इनके मोबाइल नंबर टेप करें। वीडियो बनाएं और जनता में डाल दें।

बेशक मिलावट सभी के लिए घातक है और नमूने लिए जाने चाहिए कानून के हिसाब से कम होना चाहिएऔर समानता के साथ सभी शॉपिंग मॉल में छापे मार कर उनके खाद्य वस्तुओं के नियमित रूप से नमूने भी लिए जाने चाहिए।

99३ पत्रकारों को जनहित से नहीं अपनी मोटी कमाई और स्वाहितों से सरोकार होता है। बेशक पत्रकारिता में बिना अधिकारियों पूंजीपतियों के चरण चाटे गुजारा नहीं होता।

फिर जन हितों की लड़ाई लड़ने के बाद भी अतिरिक्त क्या मिलता है?

पीएससी को धमकी तारीख नहीं बढ़ाई तो आत्मदाह

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (पीएससी) राज्य सेवा परीक्षा मेंस 2023 की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर आयोग के पास ईमेल, संदेश पहुंचे हैं, जिसमें कई धमकी भरे हैं। सोमवार से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने की बात कह चुके आंदोलनकारियों का यह आंदोलन कैसा रूप लेगा तय नहीं है लेकिन आयोग को मिली एक धमकी बहुत ही संवेदनशील है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक संदेश में आयोग को कहा गया है कि यदि मेंस की तारीख नहीं बढ़ाई गई, तो हमने एक उम्मीदवार को तैयार भी कर लिया है, जो आयोग के बाहर आत्मदाह करेगा और इसके जिम्मेदार आप होंगे।

सोमवार से फिर प्रदर्शन पर पुलिस की नजरें

इन सभी संदेशों की जानकारी पुलिस को भी दे दी गई है। इसके पहले पांच फरवरी से चला 34 घंटे का आंदोलन काफी शांतिपूर्वक हुआ था और उम्मीदवारों ने नियमों में रहकर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस बल और उच्च अधिकारियों ने भी कोई आपत्ति नहीं ली। आंदोलन आराम से पुलिस को ज्ञापन दें और आयोग से बात कर स्थगित हुआ था। लेकिन इस आंदोलन के खत्म होने के बाद नए सिर से सोमवार 11 फरवरी से प्रदर्शन की बात उठी तब आयोग के कई तरह के आपत्तिजनक संदेश आने लगे हैं। इस कारण से मामला संवेदनशील हो गया है। इसलिए यदि प्रदर्शन होता है तो पुलिस की काफी सख्त नजरें रहेंगी कि कोई अनावश्यक, गैर उम्मीदवार व असामाजिक तत्व की इसमें दखल नहीं रहें और उम्मीदवार अपनी बात शांति से रखें।

आयोग लगातार मेंस बढ़ाने के लिए विंडो तलाश रहा है

आंदोलन होने और मेंस बढ़ाने की तारीख बढ़ाने की लगातार मांग आने के बाद आयोग ने गुरुवार और शुक्रवार शाम लगातार दो दिन तक मीटिंग की और मेंस की तारीख बढ़ाने को लेकर विंडो की तलाश की। अब आयोग एक बार फिर सोमवार को फाइनल बैठक करेगा और इसमें एक बार फिर नई तारीख को लेकर विंडो की तलाश करेगा और यदि संभव नहीं हुआ तो फिर पूर्व घोषित तारीख 11 मार्च से ही परीक्षा कराने की सूचना भी औपचारिक तौर पर जारी कर दी जाएगी। कई उम्मीदवारों के संदेश आयोग के पास यह भी पहुंचे हैं कि बस वह तारीख को लेकर असमंजस दूर कर दें, ताकि हम मानसिक रूप से बेवजह परेशान नहीं हो और तैयारी पर फोकस करें, कुछ भी हो आयोग अपना स्टेंड औपचारिक तौर पर स्पष्ट करें।

आयोग के पास क्या है तारीख को लेकर विकल्प

- यदि आयोग वर्तमान शेड्यूल पर ही रहा तो फिर 11 मार्च से ही होगी परीक्षा
- आयोग यदि केवल 15-20 दिन की राहत की विंडो देखता है तो यह मार्च अंत, या अप्रैल पहले सप्ताह में संभव हो सकती है
- यदि रिजल्ट से 90 दिन की बात आती है तो फिर यह तारीख 18 अप्रैल के करीब आती है लेकिन इस दौरान लोकसभा चुनाव प्रक्रिया चरम पर होगी, ऐसे में अप्रैल से मिड मई तक परीक्षा आयोजन संभव नहीं होगा, राज्य सेवा परीक्षा 2024 प्री पर भी अभी तो आयोग की नजरें हैं, क्योंकि चुनाव शेड्यूल क्लैश होने की पूरी संभावना है।
- फिर अंत में यदि तारीख बढ़ाना ही तो एक विकल्प मई अंत से जून माह के बीच ही संभव है, लेकिन आयोग को इसमें समस्या यही आ रही है कि एक साल में पूरी परीक्षा प्रक्रिया करने का शेड्यूल मुश्किल में आ जाएगा।

हम रोबोट नहीं

कानूनी अड़चनों के चलते कुछ साल तक परीक्षाएं अधर में अटकी रहीं लेकिन 87-13 फीसदी के फॉर्मूले के बाद पीएससी लगातार परीक्षाएं आयोजित करा रहा है। साल 2019 व 2020 की भर्ती हो चुकी, साल 2021 के इंटरव्यू अप्रैल में होकर मई तक अंतिम नियुक्ति हो जाएगी, वहीं 2022 की मेंस हो चुकी है, जिसके रिजल्ट बनाने पर काम हो रहा है, फिर 2023 मेंस होना है। यानि इसी साल 2022 व 2023 की भी नियुक्ति हो जाएगी। आयोग ने दिसंबर माह में ही राज्य सेवा परीक्षा 2023 प्री ली थी, फिर जनवरी में मेंस 2022 हुई, फिर अब मेंस 2023 मार्च में होना प्रस्तावित है, अप्रैल में 2024 की प्री होना है और इस माह 2021 के इंटरव्यू होना है, फिर मई-जून में 2022 के इंटरव्यू प्रस्तावित है, यह खत्म हुए कि फिर जुलाई अंत में राज्य सेवा मेंस 2024 प्रस्तावित है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर, कराधान सहायक, राज्य वन सेवा परीक्षाएं अलग है।

आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगें अब इस तरह की है

- राज्य सेवा परीक्षा मेंस 2023 की तारीख आगे बढ़ाई जाए
- 13 फीसदी प्रोवीजनल रिजल्ट को घोषित किया जाए
- राज्य सेवा परीक्षा 2024 में 500 पद किए जाएं
- कुछ उम्मीदवार उत्तरपुस्तिकाएं दिखाने की भी मांग कर रहे हैं
- वहीं कुछ उम्मीदवार अपने अंक जानना चाहते हैं, अभी आयोग ने 2019 व 2020 में केवल चयनित उम्मीदवारों की ही सूची व अंक जारी किए हैं।
- प्री में नेगेटिव मार्किंग शुरू की जाए

साप्ताहिक समय माया

ऑनलाइन लेन-देन करो बंद... लुटेरों का अड्डा

8 साल में 11 में से पांच पेमेंट बैंक बंद

ऑनलाइन पेमेंट बहुराष्ट्रीय कंपनियों का षड्यंत्र,जनता के डाटा बेंचने, विश्लेषण, डकैती का का इंद्रजाल

बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा जनता, छोटे व्यापारियों, विक्रेताओं उद्योगों के लेन देन आदि के डाटा को एकत्रित करने और उसके बाद उन सब के डाटा का विश्लेषण आम जन की क्रय शक्ति, लेन देन, खर्च करने की क्षमता कमाई आदि का अध्ययन करके बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मोटे फायदे के लिए सभी छोटे विक्रेताओं को खत्म करने का षड़यंत्र कर रहे हैं। इसके लिए मोदी ने बहुराष्ट्रीय कंपनी के इशारे पर नाच कर 2014 में आते ही साथ सफाई के नाम देश के 2 करोड़ ठेले वालों एक करोड़ से ज्यादा फुटपाथ पर छोटे-मोटे सामानों का विक्रय करने वालों को खत्म कर दिया गया जिसका सीधा फायदा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनके शॉपिंग मॉल चलाने और उनके पैकेट गुड्स को बेचने और जनता को लूटने में मिला बदले में मोदी ने मोटा कमीशन खाया। सफाई के बाद कैशलेस के नाम पर जनता का डाटा इकट्ठा करने जो यूपीआई बैंकों की स्थापना की गई जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी गूगल पेमेंट से लेकर बड़ी-बड़ी कंपनियों नेअपने पेमेंट बैंक खोल दिए। जनता को याद होगा मोदी ने मुख्यमंत्री रहते हुए चार बार चीन की यात्रा की और प्रधानमंत्री रहते हुए तीन बारचीन की यात्रा की वहां से कोरोना कल में लगभग डेढ़ सौ अरब डॉलर लिया इसके लिए चीन ने बैंक ऑफ़ चाइना खोली।

मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए चीन से मोटा पैसा लेकर चीनी कंपनियों को गुजरात के पारंपरिक उद्योगों वस्त्र टाइल्स हीरा से लेकर मशीनरी फार्मा आदि के उद्योगों को नष्ट करने चीनी कंपनियां को गुजरात में जमा कर वहां के व्यापारियों को बर्बाद कर दिया इसीलिए व्यापारियों ने खुले में नारे लगाए हमारी भूल कमल का फूल। वही हाल भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश में चीनी कंपनियों से हजारों करोड़ हजम कर उनको जमाने कैशलेस के नाम ऑनलाइन पेमेंट का षड़यंत्र किया गया। इस कार्य में भी एक पेमेंट बैंक पेटीएम इसके बारे में राहुल गांधी ने कहा था यह पे टू मोदी है जिसमें चीन का 31% हिस्सा है।

जो सन 2016 में हुआ जिसका सार्वजनिक निर्गम लाया गया और 6 साल पुरानी कंपनी के शेयर को भी रु. 2200 में सेबी रिजर्व बैंक सब को डरा धमका जारी करवाया गया जो खुलते ही साथ रु. 12 में आ गया और वर्तमान कीमत तो गूगल पर भी नहीं दिखाई जा रही जो वास्तविकता में रिजर्व बैंक के प्रतिबंध लगाने के बाद उसका पुस्तकीय मूल्य रु. 5-6 से ज्यादा का नहीं होगा। रिजर्व

बैंक में आरोप लगाए हैं। हवाला करने के वे सभी पेमेंट बैंकों पर चाहे वह गूगल हो एयरटेल का पेमेंट बैंक हो यूपीआई भीम सभी पर लागू होता है। सब ही पेमेंट बैंक वही कर रहे हैं जो पेटीएम ने किया सभी दो नंबर के पैसे को यहां से वहां दो नंबर के धन को हवाला करने का कांड तो कर ही रहे हैं साथ ही जनता का डाटा इकट्ठा कर उसे डाटा को बेचने कर रहे हैं। हमारे युवा पीढ़ी से लेकर सभी ऑनलाइन भुगतान करने वालों से बार-बार निवेदन कर रहा हूं कि आप सारा लेनदेन नगद में ही करें जो कि सारे पेमेंट बैंक आज नहीं तो कल पेटीएम की तरह डूबेंगे और उनको रिजर्व बैंक प्रतिबंधित करेगा जैसा की भास्कर ने छापा है।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ आरबीआई की कार्रवाई ने पेमेंट बैंक इंडस्ट्री पर कई सवाल खड़े किए हैं। 2016 में लाइसेंस मिलने के बाद 11 में से 5 यानी लगभग आधे पेमेंट बैंक बंद हो चुके हैं। फंड की कमी, सीमित ऑपरेशन और आय के सीमित साधन इसकी मुख्य वजहें रहीं। आरबीआई के कठोर नियमों का पालन करने में भी इस कैटेगरी के ज्यादातर बैंक असमर्थ रहे। देश में 4 तरह के बैंक हैं- कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक और को-ऑपरेटिव बैंक।

पेमेंट्स बैंक आरबीआई का नया कॉन्सेप्ट है। फरवरी 2015 में आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक खोलने की मंजूरी मांगने वाले 41 आवेदकों की लिस्ट जारी की थी। 19 अगस्त 2015 को आरबीआई ने 11 पेमेंट्स बैंकों के आवेदन को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। सितंबर 2016 में एयरटेल पेमेंट बैंक ने देश के पहले पेमेंट बैंक के रूप में काम शुरू किया।

फिलहाल देश में सिर्फ 6 पेमेंट बैंक एक्टिव, 3 चालू ही नहीं हुए

देश में अभी सिर्फ 6 पेमेंट्स बैंक एक्टिव हैं। आदित्य बिड़ला पेमेंट बैंक 2 साल में ही बंद हो गया। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी ने पेमेंट बैंक खोलने का इरादा ही छोड़ दिया और लाइसेंस सरेंडर कर दिया। सन फार्मा के फाउंडर दिलीप संघवी ने 2016 में पेमेंट्स बैंक शुरू करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। टेक महिंद्रा ने भी ऐसा ही किया। वोडाफोन आइडिया ने भी 2019 में पेमेंट बैंक बंद कर दिया।

क्या होते हैं पेमेंट्स बैंक?

पेमेंट बैंक असल में डिजिटल कंपनियां हैं। इन्हें प्रवासी श्रमिकों, कम आय वाले परिवारों, छोटे बिजनेस, असंगठित संस्थाओं और अन्य यूज़र्स को छोटे बचत खाते और पेमेंट/रेमिटेंस सेवाएं देकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। ये दूसरे बैंकों की तरह ही काम करते हैं, लेकिन छोटे पैमाने पर और 'क्रेडिट 'जोखिम' के बिना। ये लोन या क्रेडिट कार्ड जारी जोखिम' के बिना। ये लोन या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। ये बैंक रिकरिंग या फिक्स्ड डिपॉजिट भी नहीं ले सकते। ये प्रति कस्टमर दो लाख रुपए तक सेविंग डिपॉजिट ले सकते हैं। ये डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी सेवाएं दे सकते हैं।

पेमेंट्स बैंक्स फेल होने की 6 प्रमुख वजहें

- बैंक चलाने के लिए पूंजी और फंड की कम उपलब्धता
- ग्राहकों तक सीमित पहुंच और सीमित नेटवर्क
- केवल चुनिंदा बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा पाना
- लोन और क्रेडिट कार्ड जारी करने का अधिकार न होने की वजह से कमाई के सीमित साधन
- आय की तुलना में ऑपरेशन पर ज्यादा खर्च होना
- आरबीआई के कई कड़े नियम के पालन में दिक्कत

भारत में अभी एक्टिव पेमेंट्स बैंक ये...

पेटीएम पेमेंट बैंक, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, 3 ने लाइसेंस सरेंडर कर दिया: चोलामंडलम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेस, दिलीप शांतिलाल सांघवी (सन फार्मा), टेक महिंद्रा 2 बैंक कुछ दिन में ही बंद हो गए: आदित्य बिड़ला पेमेंट्स बैंक और वोडाफोन एमपैसा लिमिटेड

सत्ता धर्मान्धता के ज़हर से देश को अंधकार में धकेल मूर्ख व पागल बनाने में कामयाब

यह कितना अदभुत देश हैं यहाँ धर्म की आड़ में जधन्य महापाप और दुर्दान्त पापाचारी भी,दैत्य व राक्षस भी,दुष्ट पिशाच व दानव भी और संहारक व भस्मासुर भी देश, दुनिया व इंसानों क़ो भी धर्मांधता की गुगली में फँसाकर गुमराह बना मूर्ख व पागल बनाने में कामयाब बन जाते हैं। यह कितना विषम हैं कि इतिहास की सबसे अधिक तबाही, भूखमरी, कंगाली, विदेशी क़र्ज़दारी में डुबाकर देश को सदी की सबसे बड़ी बर्बादी के पतन में पहुँचाने वाली इतिहास की सबसे असफल सरकार व उसका असक्षम व नाजोगा शासन भी आज अपने धृष्ट कुशासन,कुप्रबंधन व विषाक्त नीतियों से लादी प्रचण्ड बर्बादी के बवण्डर को भी छिपाने के लिए धर्मांधता के नाम पर देश को अन्धकार में ढकेल मूर्ख व पागल बनाने में कामयाब बन जाते हैं, यह कितना दुर्भाग्यशाली देश हैं कि यहाँ आज सदी की सबसे भीषण महँगाई, भयावह बेरोज़गारी, हिमालयी भ्रष्टाचार, आकाशीय आर्थिक लूटमार व सरकारी टैक्सों के बुलड़ोज़र से कुचलने को मजबूर किए जा रहे इंसान, हर व्यक्ति की क्रय शक्ति,खर्च शक्ति व बचत शक्ति को तबाह बना उन्हें करोड़ों करोड़ की तादाद में भूख व भीख पर टिकने को बाध्य बनाकर अपनी छाती पीटते नाचने वाले,कई कई सदियों तक हज़ारों पीढ़ियों को विदेशी ऋण के क़र्ज़जाल में फँसाकर तड़फाने वाले,देश को मुट्ठीभर आर्थिक लुटेरे मफ़ियाओं का दास,स्वदेशी का गला घोंट विदेशी कंपनियों के हाथों देश को गुलाम बनाने वाले, पिछले सत्तर सालों में बांधी,पाई व जुटाई सारी की सारी समृद्धि, खुशहाली, सम्पति व समृद्धि को कतरा कतरा बेचकर व चप्पा चप्पा उजाड़कर अपना चेहरा चमकाने वाले जो देश के बाजार पर चीनी साम्राज्य और सीमाओं पर चीनी क़ब्ज़े पर भी देश को झूठ से भरमाने वाले ऐसे धूर्त व मक्कार सत्ताधारी धर्मान्धता के ज़हर का राजनैतिक क़हर, हुशतंड, हंगामा व तमाशा मचाकर देश को अन्धकार में धकेल मूर्ख व पागल बनाने में कामयाब बन जाते हैं।

कविमनः **सोहन मेहता 'क्रान्ति',** जोधपुर

लाड़ली बहना योजना की वजह से विभागों के बजट में अड़ंगा, छात्रवृत्ति अटकी

शिवराज सरकार की सबसे पॉपुलर योजना लाड़ली बहना ने प्रदेश का बजट बिगाड़ दिया है। इस योजना को पूरा करने के लिए नवनियुक्त मोहन सरकार ने करोड़ों का कर्ज भी लिया। हाल ही में 10 फरवरी 2024 को मोहन सरकार ने लाड़ली बहना योजना की 9वीं किस्त जारी की। अब तक आठ किस्त जारी की जा चुकी है। लाड़ली बहनों को तो उनकी राशि मिल गई है, लेकिन इस योजना की वजह से कई विभागों के बजट में अड़ंगा लग गया है। मप्र के 5 लाख ओबीसी स्टूडेंट्स की करीब 482 करोड़ रुपए की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रुक गई है।

प्रदेश में छात्रवृत्ति अटकी

जानकारी के मुताबिक प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा ओबीसी स्टूडेंट्स की करीब 482 करोड़ रुपए की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रुक गई है। यह वो पैसा है, जो उन्होंने निजी शिक्षण संस्थानों में फीस के रूप में जमा करा दिया है। इंजीनियरिंग और मेडिकल

की पढ़ाई की पूरी फीस के साथ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स को मिलने वाला पैसा भी इसमें शामिल है। इसके साथ-साथ हॉस्टल और गैर हॉस्टल में रहने का किराया भी छात्रों को नहीं मिला है।

बार-बार नोटशीट लिखने के बाद भी नहीं मिला पैसा

वहीं इस पूरे मामले में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नोटशीट लिखने के बाद भी उनका रुका हुआ पैसा जारी नहीं किया गया है।

लाड़ली बहना योजना की वजह से कई विभागों के बजट में दिक्कत आ गई है। इसमें स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप भी शामिल है। यह इंजीनियरिंग की 30-35 हजार रुपए और मेडिकल की 5 हजार रुपए से लेकर 10 लाख तक है। बताया गया है कि कुछ पैसा 15 फरवरी के करीब जारी हो सकता है, पर नए वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही अब पूरी राशि मिलेगी।

पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रुकी

बता दें, 2021-22 में दी जाने वाली स्कॉलरशिप 350 करोड़ होती है, इसमें से 150 करोड़ ही अभी तक मिले हैं। करीब 200 करोड़ रुपए बाकी हैं। इसमें किराए और पूर्व के सालों के रिनुअल वाले प्रकरण भी शामिल हैं। मतलब 2022-23 में वित्त विभाग से कुल 482 करोड़ मिलने हैं। इसी तरह 2022-23 का 600 करोड़ तो अभी मिला ही नहीं। साथ ही 2023-24 के बजट की अभी कोई बात ही नहीं हो रही। जानकारी के मुताबिक प्री मैट्रिक की स्कॉलरशिप 250 करोड़ होती है। ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को मिल रही है। लेकिन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप रुकी हुई है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
संपादकः अजमेरा एस.पी. कुमार, मो. 9425125569, भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9425637958